आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 27.03.2026 समय : 0705

<><><><><><><>

1. सरकार ने कहा– देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं। 74 दिनों की आरक्षित क्षमता सुनिश्चित की।
2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 पहली अप्रैल, से पूरे देश और द्वीप समूह में लागू होंगे।
3. प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रंगलाल हलदर ने रंगत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दो अतिरिक्त डायलिसिस मशीनें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
4. जहाजरानी सेवा निदेशालय ने एमवी स्वराज द्वीप, एमवी कैंपबेल बे और एम वी नालंदा के संभावित यात्रा कार्यक्रम में संशोधन किया है।

<><><><><><><>

सरकार ने कहा कि भारत के पास कुल 74 दिनों की आरक्षित क्षमता है और कच्चे तेल, उत्पाद भंडार और भूमिगत भंडारों में बने विशेष कार्यनीतिक भंडारण को मिलाकर वास्तविक स्टॉक लगभग 60 दिनों का है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने फिर कहा है कि भारत में पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कमी नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि देशभर में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। घरेलू रिफाइनरी उत्पादन में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने बताया कि लगभग एक महीने की आपूर्ति पूरी तरह सुनिश्चित है और अतिरिक्त खरीद को लगातार अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार तेल कंपनियां प्रतिदिन 50 लाख से अधिक सिलेंडर सफलतापूर्वक वितरित कर रही हैं। जमाखोरी या कालाबाजारी से बचने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करके वाणिज्यिक सिलेंडरों का आवंटन भी बढ़कर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि घरेलू उत्पादन के अतिरिक्त अमरीका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों से आठ सौ हजार मैट्रिक टन एलपीजी कार्गो पहले से ही सुरक्षित है।

<><><><><><><>

भारत सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के स्थान पर नए SWM नियम 2026 लागू किए हैं। ये नियम पहली अप्रैल, से पूरे देश और द्वीप समूह में प्रभावी होंगे। इनका मुख्य उद्देश्य कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन और 'चक्रीय अर्थव्यवस्था' को बढ़ावा देना है। इसके तहत कचरे का चार श्रेणियों में वर्गीकरण कर निर्धारित केंद्रों पर जमा करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने, गलत रिपोर्टिंग करने या बिना पंजीकरण के काम करने पर पर्यावरण मुआवजा या जुर्माना लगाया जाएगा। द्वीपसमूह में अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति इन दंडों को लागू करेगी। अंडमान जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए पर्यटकों पर 'यूजर फीस' लगाई जा सकती है। होटलों और रेस्तरां के लिए विकेंद्रीकृत गीला कचरा प्रसंस्करण अनिवार्य किया गया है। केवल वही कचरा लैंडफिल में जाएगा जिसे रीसायकल नहीं किया जा सकता। बिना छंटे कचरे को लैंडफिल में डालने पर भारी शुल्क लगेगा। कचरा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी।

सभी नागरिकों, संस्थानों और स्थानीय निकायों को इन नियमों का पालन करने को कहा गया है। विस्तृत नियम egazette.gov.in पर उपलब्ध है।

<><><><><><><><>

टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत, दक्षिण अंडमान जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से कल भातूबस्ती पार्किंग क्षेत्र में एक विशेष टीबी स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त पूर्वा गर्ग के मार्गदर्शन में चलाए गए शिविर के दौरान कुल 78 व्यक्तियों की जांच की गई। शिविर का लक्ष्य शहरी संवेदनशील आबादी, विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों के बीच टीबी की जल्द पहचान करना और जागरूकता बढ़ाना है। नैदानिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सभी प्रतिभागियों का चेस्ट एक्स–रे किया गया। शिविर के दौरान नागरिकों से दो सप्ताह से अधिक समय तक लगातार खांसी, बुखार या रात में पसीना आने, बिना किसी कारण के वजन कम होने और बलगम में खून आने जैसे लक्षणों की स्थिति में तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की अपील की गई है। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर इसकी जांच और उपचार निःशुल्क है। जिला स्वास्थ्य समिति, राज्य टीबी इकाई और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के ये समन्वित प्रयास 'टीबी मुक्त वार्ड' और 'टीबी मुक्त पंचायत' को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

<><><><><><><><>

अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रंगलाल हलदर ने मध्योत्तर अंडमान के रंगत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डायलिसिस सुविधाओं की बदहाल स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान में इस केंद्र में केवल चार डायलिसिस मशीनें हैं। इनमें से भी एक मशीन बिल्लिग्राउंड के डायलिसिस रोगियों के लिए आरक्षित है। वर्तमान में लगभग 26 रोगी अपनी डायलिसिस सेवाओं के लिए सी एच सी रंगत पर निर्भर हैं। प्रत्येक डायलिसिस सत्र में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। पर्याप्त मशीनें न होने के कारण मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। पार्टी अध्यक्ष ने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से रंगत सी एच सी में कम से कम दो अतिरिक्त डायलिसिस मशीनें उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया है।

<><><><><><><><>

जहाजरानी सेवा निदेशालय की ओर से एमवी स्वराज द्वीप, एमवी कैंपबेल बे और एम वी नालंदा के संभावित यात्रा कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब एमवी स्वराज द्वीप श्री विजयपुरम से 9 अप्रैल, 14 मई और 7 जून को चेन्नई, जबकि 25 अप्रैल, 3 व 26 मई और 19 जून को विशाखापत्तनम के लिए रवाना होगा। उधर, एम वी नालंदा 2 मई को ननकौड़ी और कैम्पबेल बे होते हुए चेन्नई और 16 मई को मायाबंदर होते हुए कोलकाता के लिए प्रस्थान करेगा तथा एम वी कैम्पबेल बे 17 जून को ननकौड़ी और कैम्पबेल बे होते हुए चेन्नई जाएगा। इन सभी यात्राओं के लिए टिकटों की अग्रिम बुकिंग पहली अप्रैल से सुबह 9 बजे से जारी किए जाएंगे। टिकट ई–टिकटिंग पोर्टल के माध्यम से या स्टार्स टिकटिंग काउंटर पर सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक, जबकि शनिवार को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक बुक किए जा सकते हैं। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर रहेंगे।

<><><><><><><><>

मिडिल प्वाइंट स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन के वार्षिक स्टॉक सत्यापन का कार्य किया जाएगा। इसके चलते आज से 31 मार्च तक संस्थान में कोई भी व्यावसायिक लेनदेन या बिक्री कार्य नहीं होगा।

<><><><><><><><>

दूरदर्शन केंद्र, श्री विजयपुरम द्वारा आज लाइव फोन इन कार्यक्रम 'हैलो डॉक्टर' में महिला बांझपन – एक समग्र दृष्टिकोण विषय पर आयुष अस्पताल की चिकित्सा अधिकारी – होम्योपैथी डॉ. सुप्रिया अरंगी विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम का प्रसारण शाम साढ़े पांच बजे से किया जाएगा। दर्शक 217213 और 232434 नम्बर पर डॉयल कर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं।

<><><><><><><><>

पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग ने 'रोटेशनल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम' के तहत शहीद द्वीप और विम्बर्लीगंज में बड़े पैमाने पर चूजों, बत्तखों और ब्रॉयलर बटेर का वितरण किया। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका, स्वरोजगार और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। द्वीप पर 'ब्रॉयलर बटेर' की शुरुआत एक प्रगतिशील कदम है, जो कम समय में बेहतर मुनाफा देने वाली पोल्ट्री फार्मिंग के नए रास्ते खोलेगा। कम जगह और कम समय में तैयार होने के कारण ये छोटे किसानों के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। विभाग का लक्ष्य ग्रामीण किसानों को टिकाऊ आजीविका के विकल्प प्रदान करना और पूरे द्वीप में पोषण के स्तर में सुधार करना है।

<><><><><><><><>

अंडमान निकोबार कराटे–डो एसोसिएशन, दक्षिण अंडमान जिला ओलंपिक समिति के सहयोग से कल और 29 मार्च, को 'दक्षिण अंडमान ओपन डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप 2026' का आयोजन कर रहा है। इसमें भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी आज दोपहर दो बजे तक गूगल फार्म के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक एसोसिएशन के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए प्रतिभागी कार्यालय समय के दौरान राज्य ओलंपिक संघ से संपर्क कर सकते हैं।

<><><><><><><><>